ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 151-154**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

डिजिटल इंडिया – अंबेडकर का विजन और मोदी का प्रावधान

डॉ0 शिव प्रकाश राय,
2. हिमानी पवार

सहायक प्राध्यापक, 2. शोध अध्येत्री– राजनीति विज्ञान विभाग, सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय, गरुड, बागेश्वर (उत्तराखण्ड) भारत

Received-01.08.2026, Revised-09.08.2026, Accepted-16.08.2026, E-mail:Spraibhu@gmail.com

***सारांशः** वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय चौथी औद्योगिक क्रांति से गुजर रही है, जिसे डिजिटल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा "डिजिटल इंडिया" अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में अपने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करके नागरिकों को सरकारी सेवाएँ आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना था। इस डिजिटल इंडिया अभियान ने कई अंतःविषय क्षेत्रों को जोड़ा और उन्हें एक छतरी के नीचे लाया, जिसके परिणामस्वरूप देश के सभी वर्गों के लोगों के लिए वित्तीय लेनदेन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन, कराधान आदि सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए डिजिटल सेवाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई, 2015 डिजिटल इंडिया अभियान को शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत को हाई–स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद से जोड़ना है।*

इस डिजिटल क्रांति का मुख्य परिणाम, जिसे कई लोग समझ नहीं पाते, वह है देश में सदियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक भेदभाव की समाप्ति। भारतीय संविधान के निर्माता, बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए, जो भेदभाव में प्रमुख रूप से योगदान करते थे। अंबेडकर ने जो कल्पना की थी और जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, वह अब डिजिटल क्रांति द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रस्तुत लेख नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की डिजिटल पहलों को अंबेडकर की विचारधाराओं के साथ जोड़ता है और बताता है कि नरेंद्र मोदी अंबेडकर के भारत को कैसे साकार कर रहे हैं – समानता, स्वतंत्रता और समान अवसर की भूमि। प्रस्तुत शोध पत्र इस संकलन का प्रस्ताव करने वाला लेख है और यह प्रकाश में लाता है कि कैसे डिजिटलीकरण जैसे इंजीनियरिंग चमत्कार अंबेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में भारत को गति प्रदान कर सकता हैं। यह शोधपत्र डॉ. अंबेडकर के विचारों और कार्यों तथा सामाजिक न्याय के प्रति उनकी सिद्ध प्रतिबद्धता के बारे में पर्याप्त ज्ञान और कार्य अनुभव को भी रेखांकित करता है।

***कुंजीभूत शब्द–** डिजिटल क्रांति, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर,नरेंद्र मोदी, आर्थिक प्रगति, समानता, स्वतंत्रता,सामाजिक न्याय, लोकतंत्र।*

i. परिचय– भारतीय संविधान लोकतंत्र के दृढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान के जनक, बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र को सफलतापूर्वक पनपने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व समानता है।[1] कोई भी उत्पीड़ित वर्ग नहीं होना चाहिए और कोई भी दबा हुआ वर्ग नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित एक आदर्श समाज की कल्पना की थी। कहा जा रहा है कि, भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में कई सरकारी और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जिन्होंने कई मायनों में राष्ट्र का चेहरा बदल दिया है। ये परिवर्तन, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, देश के हर कोने में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विभाजन की गहरी जड़ें जमाने वाली बुराइयों को मिटाने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, वह साकार नहीं हुआ।

हालाँकि, भारत उस परिदृश्य को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन सभी सामाजिक परिवर्तनों में से, जिन्होंने कई मायनों में मानवता का चेहरा बदल दिया है, एक परिवर्तन जो आज दुनिया में व्याप्त है। वह है मैनुअल से डिजिटल तकनीक की ओर प्रतिमान परिवर्तन। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की ताकि एक डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाया जा सके जहां सेवाएं और शासन देश के हर नुक्कड़ और यहां तक कि अंतिम नागरिक तक बिना किसी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के पहुंच सकें।[2,3] दैनिक सेवाओं के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट के उपयोग की घोषणा और सरकार के नेतृत्व में एक जोरदार डिजिटल आंदोलन ने डिजिटलीकरण का लाभ उठाने वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि देखी है। शहरी क्षेत्रों में 60 करोड़ से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और भारत ने 2019 से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 45% से अधिक की वृद्धि देखी है; 2010 से 2020 तक स्मार्टफोन के उपयोग में 54ः की वृद्धि हुई है;[4] यह एक ज्वालामुखी वृद्धि है।

लगभग सभी सेवाएँ जो कभी मनुष्यों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती थीं, अब डिजिटल तकनीक द्वारा पूरी की जा रही हैं; इस प्रकार लोगों और शासन के बीच डिजिटल विभाजन मिट गया है। डिजिटल विभाजन को शून्य करने का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक और आर्थिक विभाजन को शून्य करना है। डिजिटलीकरण ने भेदभाव को लगभग समाप्त कर दिया है। अमीर और गरीब, बहिष्कृत और उच्च जाति सभी को अब सभी सेवाओं तक समान पहुंच है। डिजिटल इंडिया के वास्तुकार, प्रधान मंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के रूप में एक उदाहरण स्थापित किया है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है5। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत की आर्थिक उन्नति और जीवन की गुणवत्ता के लिए प्रावधान किया है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के रास्ते में आने वाले भेदभाव और भ्रष्टाचार की सामाजिक बुराई को भी मिटा दिया है और सभी वर्गों के लोगों के लिए सरकार की सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाई है। जो काम अंबेडकर अपने जीवनकाल में हासिल नहीं कर सके, जो काम उनके उत्तराधिकारी भारत की आजादी के सात दशकों से अधिक समय में हासिल नहीं कर सके, वह अब डिजिटल क्रांति द्वारा मात्र सात वर्षों में हासिल किया जा रहा है।

यह पेपर भारत में डिजिटलीकरण के माध्यम से मानव उन्नति के लिए नरेंद्र मोदी के प्रावधानों के साथ अंबेडकर की विचारधारा को जोड़ता है और बताता है कि परिणामी उन्नति अंबेडकर की विचारधारा को कैसे साकार करती है। यह पेपर इस तरह के संकलन का प्रस्ताव करने वाला पहला पेपर है, जो यह प्रकाश में लाता है कि कैसे डिजिटलीकरण (इंटरनेट पर सभी जानकारी सुलभ बनाना) और डिजिटलीकरण (इंटरनेट पर सभी सेवाओं को सुलभ बनाना) का इंजीनियरिंग चमत्कार समानता और स्वतंत्रता के साथ अंबेडकर का भारत बना सकता है।[5] लंबे समय से लोगों ने सोचा है कि अंबेडकर की विचारधाराओं को नीति निर्माण, कानूनी

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

निर्माण और शिक्षा जैसे सामाजिक साधनों से हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह पेपर अंबेडकर की विचारधाराओं को एक सप्तवर्षीय से भी कम समय में साकार करने के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की जबरदस्त शक्ति को प्रकट करता है।

यह शोधपत्र अंबेडकर के सपने को साकार करने की दिशा में भारत में डिजिटल क्रांति के प्रभाव की समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करता है। खंड II में भारत के लिए अंबेडकर के सपने का वर्णन किया गया है। अगले दो खंड (III और IV) भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और पिछले सप्तम में इसके प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं। खंड V में अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से बनाए गए प्रावधानों पर चर्चा की गई है। इन चर्चाओं के दौरान, डॉ. अंबेडकर के विचारों और कार्यों और सामाजिक न्याय के लिए सिद्ध प्रतिबद्धता पर पर्याप्त ज्ञान और कार्य अनुभव को भी रेखांकित किया गया है। समापन टिप्पणियाँ खंड VI में प्रस्तुत की गई हैं।

मशहूर संगीतकार इलैयाराजा ने अपनी नई किताब में पीएम मोदी की तुलना अंबेडकर से की है और उन्हें 'अद्भुत व्यक्तित्व' बताया है। किताब की प्रस्तावना में की गई इस तुलना की डीएमके ने कड़ी आलोचना की है। इलैयाराजा ने अंबेडकर को रिफॉर्मर और मोदी को परफॉर्मर बताया है।

ii, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और उनका विजन– इस लेख का मुख्य उद्देश्य श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रावधान के तहत भारत सरकार की डिजिटल तकनीकी उन्नति के सामंजस्य को एक सदी पहले एक व्यक्ति के अथक प्रयासों से मिलाना है, जो भारत को समान अवसरों की भूमि के रूप में देखता था। यह लेख पिछले दशक में भारत के लोगों पर डिजिटल तकनीक के सकारात्मक प्रभाव को प्रकाश में लाता है और नरेंद्र मोदी के डिजिटल उन्नति के प्रावधान के माध्यम से अंबेडकर की अंतर्निहित विचारधारा को वास्तविकता में लाने के आधार पर तर्क देता है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को इंदौर के पास महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर हुआ था। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा।[6,7] चूंकि उनके माता–पिता दलित थे, इसलिए उन्हें समान अवसर नहीं दिए गए। अपने बढ़ते वर्षों के दौरान, उन्हें कई चुनौतियों और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षकों और अन्य छात्रों ने भीमराव अंबेडकर के साथ हीन व्यवहार किया। फिर भी उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन में हर बाधा को प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से पार किया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे एक प्रतिभाशाली छात्र, एक प्रतिष्ठित विद्वान, अर्थशास्त्री, वकील, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और बैरिस्टर थे।

iii. डिजिटल इंडिया पहल– भारत पिछले सात वर्षों में आर्थिक सुधारों, शहरीकरण और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। हालाँकि विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक डिजिटल तकनीकी उन्नति है जो लोगों के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। यह तकनीकी उन्नति समाज के सभी सामाजिक और वित्तीय स्तरों के माध्यम से निर्बाध सूचना, नकदी और सेवा प्रवाह की ओर ले जाती है और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसलिए यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज के समय में, किसी देश का विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक और सामाजिक विकास उसके डिजिटल तकनीकी कौशल के इर्द–गिर्द घूमता है। डिजिटल इंडिया 1 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की सेवाएँ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (संक्षेप में ई–गवर्नेंस कहा जाता है) ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर उपलब्ध कराई जाएँ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है, ताकि देश के सभी वर्गों को उनकी जाति, पंथ, भाषा और लिंग के बावजूद डिजिटल सेवाएं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य को सस्ती, विकासात्मक और समावेशी तकनीक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस पहल के तहत 123 करोड़ से अधिक आधार, 120 करोड़ मोबाइल फोन और 3.12 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSc) आदि का प्रसार हुआ है। आधार, BHIM&UPI, GSTN और GeM जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने निजी क्षेत्र के नवाचार के साथ मिलकर भारत में डिजिटल अपनाने में तेजी लाई है।[8]

iv. इस सप्तवर्षीय में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर डिजिटल इंडिया पहल का प्रभाव– यह खंड कई में से चार प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों का विवरण देता है, जहाँ अंबेडकर की विचारधारा नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल द्वारा पूरी होने की राह पर है।

क) डिजिटल लेन–देनः 8 नवंबर, 2016 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। उस ऐतिहासिक निर्णय के कई कारण थे। उनमें से एक कारण डिजिटल इंडिया के सपने की ओर कदम बढ़ाना था। मौद्रिक लेन–देन का पारंपरिक रूप लोगों के बीच भौतिक हार्ड कैश के आदान–प्रदान के साथ होता है। कैशलेस इंडिया ने अब इसे लगभग बेमानी बना दिया है। कैशलेस अर्थव्यवस्था वह है, जिसमें सिस्टम के माध्यम से तरल लेन–देन प्लास्टिक मुद्रा के आदान–प्रदान या डिजिटल भुगतान के माध्यम से होता है। एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रचुर आगमन प्लास्टिक मुद्रा है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के आगमन ने भी कैशलेस अर्थव्यवस्था की बारीकियों को फिर से परिभाषित किया है। डिजिटल भुगतान के प्रमुख लाभों में पारदर्शिता और अघोषित धन में कमी शामिल है।

ख) डिजिटल शिक्षाः डिजिटल शिक्षा आधुनिक तकनीक और डिजिटल उपकरणों का अभिनव समावेश है जो शिक्षण और सीखने की प्रगति में सहायता करता है। यह अवधारणा नई नहीं है और कई वर्षों से विभिन्न रूपों में मौजूद है, लेकिन जब कोविड–19 महामारी ने आमने–सामने शिक्षण को निलंबित कर दिया तो इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। अधिकांश शैक्षणिक संस्थान डिजिटल शिक्षा को एक समाधान के रूप में अपना रहे हैं, जबकि पारंपरिक कक्षा व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित महामारी के कारण कुछ समय के लिए पीछे हट जाती है।

ग) डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँः कोविड–19 प्रकोप ने हर देश को अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की सीमाओं से दर्दनाक रूप से अवगत कराया है। महामारी के चरम के दौरान डिजिटल क्रांति और टेलीहेल्थ समाधान अनिवार्य हो गए। 2021 में ऑनलाइन परामर्श लेने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर लगभग 40 करोड़ हो।[9] उदाहरण के लिए, ई–कॉमर्स पोर्टल पर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर देने वाले देश की संख्या 2025 तक लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने डिजिटल चिकित्सा को बढ़ावा दिया है। आयुष्मान भारत मिशन का लक्ष्य 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना और सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में

चिकित्सा उपचार के लिए प्रति वर्ष पाँच लाख का बीमा प्रदान करना है।[10] मिशन में अस्पताल या डॉक्टर के कार्यालय के माध्यम से कैशलेस भुगतान और कागज़ रहित रिकॉर्ड रखना शामिल है। परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

घ) डिजिटल गवर्नेंसः भारत ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से पिछले 7 वर्षों में शासन में एक बड़ा बदलाव देखा है। सभी सरकारी सूचनाओं को डिजिटल बनाने और सभी सेवाओं को डिजिटल बनाने से लोगों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग और भाषा के बावजूद सभी योजनाओं से सीधे लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा लोगों को सीधे धन वितरित करने से शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और बेहिसाब धन में कमी आई है। इस डिजिटल सुधार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सभी भारतीयों को सशक्त बनाया है, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण किया है और भ्रष्टाचार को कम किया है।

v. अंबेडकर की विचारधारा और डिजिटल इंडिया पहल का संकलन – अंतःविषय, विचार और चर्चाः डिजिटल इंडिया पहल के तत्वावधान में नरेंद्र मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रावधान राष्ट्र के अंबेडकर के सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। यह खंड प्रस्तुत करता है कि नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल द्वारा अंबेडकर के भारत को कैसे साकार किया जा रहा है।

अंबेडकर की विचारधाराएँ और विजन– "मुझे वह धर्म पसंद है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।" बाबासाहेब अम्बेडकर। सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। "हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिल रही है? हमें यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिल रही है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों का ईंधन है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है" बाबासाहेब अंबेडकर।

जाति, लिंग, भाषा और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव ने भारत के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। अंबेडकर ने न केवल जातिगत असमानता के मुद्दों पर लिखा था, बल्कि भारत में इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी, खासकर दलितों के रूप में जाने जाने वाले पूर्व अछूतों/सामाजिक बहिष्कृत लोगों के मानवाधिकारों के लिए। उनके अनुसार, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए।

अंबेडकर भारतीय बहिष्कृत लोगों, दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठोस वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के संघर्ष में निकटता से शामिल थे। वे लंदन में गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे, जहाँ उन्होंने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के लिए तर्क दिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 1949 के भारतीय संविधान में विधायी, रोजगार और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण के रूप में गारंटी दी गई। बाबासाहेब अंबेडकर भारत में सामाजिक असमानताओं पर काबू पाने के लिए एक महान चैंपियन थे। वे दलित वर्ग के आंदोलन को पूरे भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन में बदलने में सफल रहे।

• **समान अवसर के साथ एक स्वस्थ अर्थव्यवस्थाः** अंबेडकर उन अग्रदूतों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक चर के बीच संबंधों और भारत को बदलने में विकास परियोजनाओं की भूमिका की जांच की। उनकी विचारधारा थी कि औद्योगीकरण और कृषि विकास अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। वे पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सार्वजनिक वित्त, कराधान और ब्रिटिश भारत के मौद्रिक मानकों का व्यापक अध्ययन किया और ब्रिटिश भारत में स्थानीय व्यापार पर आंतरिक और बाहरी दोनों करों के प्रतिकूल प्रभावों की व्याख्या की। उन्होंने ग्रामीण गरीबी, हाशिए पर आर्थिक उछाल, पिछड़े औद्योगिक विकास पर व्यापक अध्ययन किया और हाशिए पर पड़े और दलितों के उत्थान के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के तहत समाधान और कर नीतियों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए आयकर का विरोध किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। उन्होंने भूमि सुधार और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबासाहेब अंबेडकर ने आर्थिक सुधारों के निर्णय लेने के ढांचे में सरकारी हस्तक्षेप के लिए अभियान चलाया और कहा कि सरकार के हस्तक्षेप न करने का मतलब निजी निरंकुशता होगी। उन्होंने सभी लोगों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं के भीतर वित्तीय समानता के लिए अथक प्रयास किया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला।

• **महिला सुरक्षा और लैंगिक समानताः** अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल में सुधार किया, जिसमें गैर–हिंदुओं पर भी कानून लागू करना शामिल था। इस बिल के अनुसार, बेटियों को विरासत का हिस्सा दिया जाएगा, जबकि विधवाओं को संपत्ति का पूरा अधिकार दिया जाएगा, जो पहले प्रतिबंधित था। इस प्रकार बिल ने विरासत और विवाह के कानूनों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाया। बाबासाहेब अंबेडकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि महिलाओं को श्रम कानूनों के तहत भी सुरक्षा मिले। उन्होंने काम के घंटों की संख्या कम करने और काम करने की स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1928 में, बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में, उन्होंने कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले बिल का समर्थन किया। भारतीय महिला आंदोलन के लिए अंबेडकर ने एक नारीवादी राजनीतिक एजेंडा तैयार करने के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत प्रदान किया, जो समकालीन सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था में वर्ग, जाति और लिंग के मुद्दों को एक साथ संबोधित करता है। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक सुधार और प्रावधान किए। उन्होंने हिंदुओं और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्य वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता तैयार की। उन्होंने संकेत दिया कि महिलाओं को सर्वांगीण विकास दिया जाना चाहिए, खासकर सामाजिक शिक्षा, उनकी भलाई और सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाज के हर वर्ग की भारतीय महिलाओं को उनका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए और महिलाओं के आत्मसम्मान और संयम को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने महिलाओं को मजबूत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। अंबेडकर ने भारत के राजनीतिक शब्दावली और संविधान में महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया।

• **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँः** दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने सही कहा है, "बाबासाहेब हर बच्चे के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहते थे।" अंबेडकर इस विश्वास के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति को जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती है, चाहे वे सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक प्रकृति की हों। उन्हें विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। वे दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में पहले पीएचडी और अर्थशास्त्र में पहले डबल डॉक्टरेट धारक थे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक थे। हालाँकि, अंबेडकर ने बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का अनुभव किया और उन्होंने हाशिए के लोगों को शैक्षिक और स्वास्थ्य आरक्षण प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

vi. निष्कर्ष– इस शोधपत्र में इस बात का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया भारत के लिए अंबेडकर के सपने को साकार कर रहा है। अंबेडकर ने सभी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध वकालत की तथा सरकारी निगरानी और जवाबदेही के साथ एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की डिजिटल इंडिया पहल भारत के सभी वर्गों के लोगों को लगभग सभी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से और निर्बाध रूप से प्रदान कर रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन और कैशलेस लेन–देन की अवधारणा शामिल है, पिछले सप्तम में आर्थिक विकास और नागरिक सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं। वर्तमान में, यह पहल धीरे–धीरे और लगातार अंबेडकर के सपने को साकार कर रही है। यह कैसे साकार हो रहा है, इस शोधपत्र में कैशलेस लेन–देन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन के पहलुओं और पिछले सप्तम में उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अंत में डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए उनकी सिद्ध प्रतिबद्धता पर लेखक का पर्याप्त ज्ञान और व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रस्तुत किया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने, समान अवसरों के साथ स्वस्थ अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की विचारधारा डिजिटल इंडिया पहल और सूचना प्रौद्योगिकी में अन्य प्रगति के माध्यम से साकार हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches, Vol 1, Vasant Moon, Dr. Ambedkar Foundation Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, 1979.
2. India's Trillion Dollor digital economy, Report of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, 2018.
3. Manikanta, "Digital India Program and impact of digitisation in improving quality of life in citizens," Adarsh Journals, pp. 11-15, 2017.
4. Smartphone penetration rate in India from 2010 to 2020, with estimates until 2040, Shangliao Sun, 2022.
5. Digital India empowered people by making technology more accessible, says PM Modi; launches 'Digital India Bhashini 'to provide easy access to internet & digital services in Indian languages, Newsonair, July 4, 2022.
6. Ambedkar, Bhim Rao. "Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 7." Government of Maharashtra, Bombay, 1990.
7. Campion, Sonali. "Educate, agitate, organise: a short biography of Dr BR Ambedkar." South Asia LSE, 2016.
8. Nitisha Dubey, Digital India Programme and its Impact, BISINFOTECH, January 28, 2021. Nitisha Dubey January 28, 2021.
9. E-Governance & Telemedicine, Chapter 20, Report of the Ministry of Health and Family Welfare, 2019.
10. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia.. Report on evolution of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia, 2022.

*****